क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 1 अंक: 240, सोमवार, 25 सितम्बर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

भारत में प्रति दस लाख लोगों पर हैं 19 न्यायाधीश : कानून मंत्रालय के आंकड़े

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत में प्रति दस लाख लोगों पर 19 न्यायाधीश हैं और देश में 6000 से अधिक न्यायाधीशों की कमी है जिनमें से 5000 से अधिक न्यायाधीशों की निचली अदालतों में कमी है। कानून मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक जनसंख्या का अनुपात प्रति 10 लाख लोगों पर 19.49 न्यायाधीश हैं। यह आंकड़ा उस दस्तावेज का हिस्सा है जिसे संसद में चर्चा के लिए मार्च में तैयार किया गया था। दस्तावेज कहता है कि अधीनस्थ अदालतों में 5748 न्यायिक अधिकारियों की कमी है और 24 हाई कोर्ट में 406 खाली पद हैं। निचली अदालतों में फिलहाल 16,726 न्यायिक अधिकारी हैं जबकि वहां 22,474 न्यायिक अधिकारी होने चाहिए थे। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की मान्य संख्या 1079 हैं जबकि वहां मात्र 673 न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 31 हैं और वहां छह रिक्तियां हैं। इसी तरह, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में न्यायाधीशों के 6160 पद खाली हैं। न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात पर बहस को अप्रैल, 2016 में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर ने तब हवा दे दी थी जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुकदमों के पहाड़ से निबटने के लिए न्यायाधीशों की संख्या 21,000 से बढ़ाकर 40,000 करने में सरकार की निष्क्रियता पर अफसोस प्रकट किया था और कहा था, आप सारा बोझ न्यायपालिका पर नहीं डाल सकते। उन्होंने कहा था कि 1987 में जब विधि आयोग ने प्रति दस लाख लोगों पर न्यायाधीशों की संख्या दस से बढ़ाकर 50 करने की सिफारिश की थी तब से अबतक कुछ भी आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन बाद में सरकार ने इस तरफ इशारा किया कि 245वीं रिपोर्ट में विधि आयोग ने कहा कि प्रति व्यक्ति द्वारा दायर मामलों की संख्या भौगोलिक इकाइयों में घटती-बढ़ती है क्योंकि मामले दाखिल करने का जनसंख्या के आर्थिक और सामाजिक हालत से संबंध होता है। हाल ही में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 24 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से निचली अदालतों में न्यायायिक अधिकारियों की नियुक्त में तेजी लाने की अपील की थी क्योंकि बड़ी संख्या में मामलों के लंबित होने की वजह न्यायाधीशों की कमी है।

रोडरेज में कार सवार ने युवक को ढाई किलोमीटर तक घसीटा, मौत

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में शनिवार रात ह्न॥-9 पर गणेश विसर्जन के जुलूस में शामिल एक स्कूटी सवार को कार ने टक्कर मार दी। जुलूस में शामिल युवकों ने कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। चालक कार को लेकर भागने लगा तो एक युवक कार को रोकने के लिए बोनट पर चढ़ गया। चालक बोनट पर चढ़े युवक को घसीटते हुए करीब ढाई किलोमीटर तक ले गया। जहां युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 23 वर्षीय राहुल राज के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार राहुल परिवार के साथ पांडव नगर के एस ब्लॉक में रहता था। उसके परिवार में पिता मुन्ना लाल, मां और भाई अमित और मोहित हैं। राहुल एक निजी कंपनी में काम करता था। राहुल के दोस्त उमेश ने बताया कि शनिवार शाम रात 9:15 बजे पांडव नगर के एस ब्लॉक स्थित शिव मंदिर से गणेश विसर्जन का जुलूस डीएनडी फ्लाईओवर तक के लिए निकला। इस दौरान जुलूस में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली और करीब 15 बाइक व स्कूटी शामिल थी। अधिकांश लोग पैदल ही चल रहे थे। राहुल भी पैदल चल रहा था। तभी गाजियाबाद की तरफ से आ रही एक कार जुलूस में शामिल स्कूटी सवार युवक को टक्कर मार दी। जूलुस में चल रहे लोगों ने कार सवार पर हमला कर दिया। कार के शीशे और बंपर तोड़ने लगे। चालक वहां से कार लेकर भागने लगा। तभी राहुल कार को रोकने के लिए बोनट पर चढ़ गया। चालक तेजी से कार को लेकर भागने लगा। राहुल कार से घसीटता हुआ कार के साथ जाने लगा। जुलूस में शामिल बाइक सवारों ने कार का पीछा किया। इस दौरान कार ने एक-दो लोगों को और टक्कर मारी। बाइक सवार पीछा करते जब मयूर विहार में क्रॉउन होटल के पास पहुंचे तो वहां राहुल सड़क किनारे खून से लथपथ पड़ा था। राहुल को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में लेकर गए। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

माकन का इस्तीफे से इनकार

सपा का सामाजिक न्याय यात्रा रैली से लोकसभा चुनाव का शंखनाद

देश में जाति की आबादी के हिसाब से संसाधनों पर हिस्सेदारी तय करने का शिगूफा

मंच पर अखिलेश-मुलायम दिखे एक साथ, मोदी और योगी पर किए प्रहार

नई दिल्ली, एजेंसी। लगभग एक सप्ताह से जारी इस्तीफे की अफवाह के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि इलाज के लिए सिंगापुर जाने के पूर्व पार्टी नेतृत्व को उन्होंने इसकी सूचना दे दी थी। वह पार्टी के नेतृत्व के निर्णय का पालन करेंगे। माकन ने कहा कि वे दिल्ली के मुद्दे पर लगातार संघर्ष करेंगे। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने जैसी कोई बात नहीं कही।

महिपालपुर के पास रंगपुरी में सीलिंग के खिलाफ आयोजित रैली के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अजय माकन ने कहा कि इलाज के लिए विदेश जाने के पूर्व पार्टी नेतृत्व को उन्होने सूचना दे दी कि वे बीमार हैं व शत प्रतिशत फिट नहीं हैं, लेकिन वे पार्टी नेतृत्व के निर्णय का पूरा सम्मान करेंगे। सिंगापुर में माकन ने पीठ में भारी दर्द पर विशेषज्ञ डाक्टरों की राय ली। इसके पूर्व उनका इलाज एम्स में चल रहा था। माकन पीठ व रीढ़ में दर्द से परेशान हैं लेकिन सीलिंग के खिलाफ गांधी नगर, त्रिनगर, करोल बाग व रंगपुरी सहित चार रैली को संबोधित कर चुके हैं। सीलिंग के खिलाफ सभी रैलियों में भारी भीड़ से कांग्रेस नेतृत्व उत्साहित है। इसके पूर्व दिल्ली के प्रभारी पीसी चाको भी अजय माकन के इस्तीफे को नकार चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी में समाजवादी पार्टी (सपा) की सामाजिक न्याय यात्रा रैली से न सिर्फ आगामी लोकसभा चुनाव 2019 का शंखनाद हो गया है। बल्कि चुनाव के दौरान जाति कार्ड खेलने के इरादे भी जाहिर हो गए हैं। रविवार को आयोजित साइकिल रैली के दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अब वक्त आ गया है, जब जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए ताकि उसके मुताबिक संसाधनों पर हिस्सेदारी तय हो सके। वहीं, मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अब देश में जातिवार जनगणना हो ही जानी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि देश में किस जाति की कितनी आबादी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा आधे-अधूरे आंकड़ों के साथ जनता को पूरा न्याय नहीं मिल सकता है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश और साथियों के प्रयासों का ही नतीजा है कि बारिश के बाद भी इतनी भीड़ आई है कि मैदान छोटा पड़ गया। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा थी कि सपा कभी बूढ़ी न होने पाए। नौजवानों की इस तादाद से साबित होता है कि ऐसा नहीं हो सकेगा। मेरा कहना है कि अगर 15 लाख नहीं दे सकते हो तो हर साल तीन-तीन लाख दे दो इसके साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि महिलाओं को विशेष अवसर देना सपा का लक्ष्य है। हालांकि आज की रैली में महिलाएं कम ही संख्या में आई थीं लेकिन उन्हें भी आगे नहीं आने दिया गया। अखिलेश यादव ने राफेल मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने राफेल मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाने की मांग की। साथ ही कहा कि जेपीसी के बिना सच्चाई सामने नहीं आएगी। अब यह मुद्दा नियंतग्र हो गया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सीएम से शुगर के बारे में कहते हैं तो वह कहते हैं कि गन्ना कम उगाओ। ज्यादा गन्ना पैदा करते हैं इसलिए डायबिटीज हो रही है। जब उनसे कहते हैं कि बंदर भगाओ तो वे कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ो, अपने आप भाग जाएंगे। यही नहीं नौकरियों में भर्ती के दौरान हम पर आरोप लगता था, लेकिन अब जो नियुक्तियां हो रही हैं। वो देख लो। अस्पतालों में जाति पूछने के बाद इलाज होता है।

दो दिन की बारिश ने कई राज्यों में मचाई तबाही, अलर्ट जारी

नई दिल्ली, एजेंसियां। उत्तर भारत में पिछले दो दिनों की बारिश ने भारी तबाही मचाई है। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है जहां कई लोगों की जान चली गई। हवाई, रेल और सड़क यातायात बाधित रही। उत्तराखंड में सोमवार को भूस्खलन से बदरीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री जाने वाले मार्ग बाधित रहे। बारिश-बर्फबारी से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।

उत्तराखंड: भारी बारिश की संभावना

उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिकेश बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, रुद्रप्रयार में ऋषिकेश केदारनाथ हाईवे, उत्तरकाशी में ऋषिकेश यमुनोत्री हाईवे बंद है। इन बड़े राजमार्गों के अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में 45 ग्रामीण मार्ग भी अवरुद्ध हैं। इस बीच, मौसम विभाग ने उत्तराखंड में कहीं-कहीं विशेषकर देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ और बागेश्वर जिलों में अगले 24 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।

हिमाचल: बारिश-बर्फबारी से जनजीवन ठहरा

हिमाचल प्रदेश में पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश से हवाई सेवा प्रभावित रही। हिमाचल तथा चंडीगढ़ को न तो बाहर से कोई उड़ान आई और न ही गई। कई सड़क तथा पुल बह गए। रावी, ब्यास, सतलुज नदियां उफन पर हैं। वहीं, लाहौल-स्पीति, किन्नौर और कुल्लू में भारी हिमपात से काजा, लेह और मनाली मार्ग पर सैकड़ों लोग-पर्यटक फंसे रहे। बर्फबारी से राज्य में पारा 6 से 8 डिग्री नीचे गिरा है। लाहौल-स्पीति में बर्फबारी के बाद बर्फ की मोदी चादर बिछी है। जिले के केलांग में तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है।

संचार सेवा ठप:

मोबाइल-बिजली और संचार सेवा ठप रही। राज्य के ज्यादातर जिलों में सोमवार को स्कूल बंद रहे। बाढ़ के पानी में बह जाने से कांगड़ा और कुल्लू में दो लोगों की जान चली गई। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में कुछ सुधार की संभावना है तथा 26 सितंबर तक बारिश के आसार हैं।

हिमाचल: कहां-कितनी बारिश

डलहौजी	170 मिमी
मनाली	121 मिमी
कांगड़ा	120.08 मिमी
धर्मशाला	62.6 मिमी
शिमला	23.1 मिमी

जम्मू-कश्मीर: भूस्खलन से पांच की मौत

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में भूस्खलन के चलते मिट्टी का घर ढह जाने से सोमवार को एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भागीदारी किसी देश के खिलाफ नहीं

नई दिल्ली ■ एजेंसी।

अगले महीने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे से पहले भारत ने रूस से साफ कहा है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी भागीदारी किसी देश के खिलाफ नहीं है और वह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वृहद ढांचे का इच्छुक है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

दरअसल, अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की बड़ी भूमिका के लिए प्रयासरत है, जिसे कई देश क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल को रोकने के प्रयास के रूप में देख रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भागीदारी का मुद्दा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तथा उनके रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के बीच बातचीत में प्रमुखता से उठा।

सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिंद-प्रशांत के लिए 'समग्रता के नजरिए' को स्वीकारते हुए रूसी पक्ष ने महसूस किया कि ऐसे देश हो सकते हैं जो अपने हितों को पूरा करने के लिए हिंद-प्रशांत कॉन्सेप्ट में 'हेरफेर' करने का प्रयास कर रहे हों। हालांकि स्वराज ने स्पष्ट रूप से लावरोव से कहा कि भारत ने हमेशा जिम्मेदारी से काम किया है और वह हिंद-प्रशांत क्षेत्र की शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सभी को साथ लाने का प्रयास कर रहा है। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत की भागीदारी किसी देश के खिलाफ नहीं है। पुतिन अगले महीने भारत आनेवाले हैं और सालाना भारत-रूस समिट के दौरान हिंद-प्रशांत क्षेत्र के सुरक्षा हालात पर चर्चा हो सकती है। पिछले साल नवंबर में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने लंबित चतुष्कोणीय गठबंधन को आकार दिया था। इसका मकसद हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख समुद्री मार्गों को किसी के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए नई रणनीति तैयार करना बताया गया है।

भारत के साथ नवंबर में औपचारिक सम्मेलन नहीं करेगा आसियान

नई दिल्ली। जब भारत ने गणतंत्र दिवस पर आसियान के 10 नेताओं को न्योता दिया था तो इसे अंदाजा नहीं था कि आसियान नवंबर में भारत के साथ दूसरा सम्मेलन आयोजित करने से इनकार कर देगा। यह तब जाकर पता चला जब चीन, जापान और अन्य साझीदारों के साथ नवंबर में बैठक करने जा रहे आसियान की तरफ से बताया गया कि भारत के साथ सम्मेलन हर साल की तरह औपचारिक नहीं होगा। आसियान के नियमों के मुताबिक, क्षेत्रीय ग्रुप बाहरी साझेदारों के साथ साल में दो बैठक नहीं करता। आसियान के 10 राष्ट्राध्यक्ष गणतंत्र दिवस पर भारत में थे और जनवरी में सम्मेलन हुआ था, तो फिर नवंबर में भारत के साथ कोई औपचारिक बैठक नहीं होगी। इसका मतलब है कि भारत ईस्ट एशिया सम्मिट का हिस्सा होगा, लेकिन भारत के साथ औपचारिक बैठक नहीं होगी। विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने आसियान नेतृत्व को संदेश भिजवाया कि अगर भारत के साथ सम्मेलन नहीं होगा तो पीएम मोदी सिंगापुर नहीं जाएंगे। यह देखना भी अजीब होता अगर भारत नवंबर में खुद को सिंगापुर सम्मेलन से दूर रखता, विशेषकर तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस सम्मेलन से दूर रहने वाले हैं। इस कूटनीतिक शोर-शराबे का नतीजा था कि अब पीएम मोदी नवंबर 11-15 के बीच सिंगापुर में आसियान नेताओं के साथ अनौपचारिक ब्रेकफास्ट मीटिंग करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, आसियान के मौजूदा अध्यक्ष होने के नाते सिंगापुर इस नियम को लागू करने और क्षेत्र के बाहर सम्मेलन कराने पर प्रतिबंध के पक्ष में है।

दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश- मुर्गा मंडी में अब से नहीं कटेंगे मुर्गे

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने गाजीपुर मुर्गा मंडी में मुर्गा काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि गाजीपुर मुर्गा मंडी में सिर्फ मुर्गा बेचने की ही अनुमति है मुर्गा काटने की नहीं। हाई कोर्ट ने सरकार और अन्य संबंधित विभाग को एक हफ्ते के अंदर आदेश का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। इससे पहले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने कहा कि मंडी में नियमों की अनदेखी कर मुर्गा काटा जाता है। समिति ने 24 अप्रैल को ही मंडी में मुर्गा काटने पर रोक लगाने का आदेश दिया था। एनिमल राइट पर काम करने वाली गौरी मुलेखी ने हाई कोर्ट पर गाजीपुर मुर्गा मंडी में मुर्गा कटने के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल किया था। जिस पर हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि गाजीपुर मुर्गा मंडी में अवैध रूप से मुर्गा की कटाई होती है। जिससे वहां पर संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।

सीलिंग के विरोध

राजधानी में सीलिंग के विरोध रंगपुरी गांव (महिपालपुर) में आयोजित महापंचायत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन के साथ मंच पर पूर्व विधायक मुकेश शर्मा, सुरेंद्र कुमार व अन्य नेतागण।

ट्रेन ऑपरेटर ने दिखाई मानवता, पक्षी बचाने की खातिर रोकी दिल्ली मेट्रो

नई दिल्ली। एक पक्षी को बचाने की खातिर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं कालिंजी कुंज मेट्रो स्टेशन पर कुछ समय के लिए बाधित रहीं। पक्षी पटरियों पर गिरा हुआ था। एक वन्यजीव संरक्षण एनजीओ ने सोमवार को यह जानकारी दी। वाइल्डलाइफ एसओएस स्पेशल प्रोजेक्ट्स के प्रबंधक वसीम अकरम ने बताया कि यह घटना रविवार को हुयी। उन्होंने बताया कि पक्षी का इलाज किया जा रहा है। एनजीओ के अनुसार दिल्ली मेट्रो ने रविवार को उसे सूचना दी कि एक पक्षी पटरी पर गिरा हुआ है। एक ट्रेन आपरेटर ने पक्षी को देखा जो नहीं उड़ पा रहा था। ऐसे में पूरी आशंका थी कि वह किसी ट्रेन की चपेट में आता। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश- मुर्गा मंडी में अब से नहीं कटेंगे मुर्गे एनजीओ ने बताया कि दो बचावकर्मियों की एक टीम आवश्यक उपकरण के साथ वहां भेजी गयी। उसके बाद पक्षी (इंडियन कार्मोरेंट) को मेडिकल सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

योजना सुरंग बनने से 60,000 कारों का ट्रैफिक और भैरों मार्ग पर 55,000 कारों का रोजना ट्रैफिक कम हो सकेगा

मथुरा रोड को ट्रैफिक फ्री करने बनेगी एक किमी लंबी सुरंग

नई दिल्ली,(एजेंसी)।

प्रगति मैदान रीडिवेलपमेंट प्रॉजेक्ट में सड़क निर्माण का कार्य भी शामिल है। इससे अगले साल के आखिरी तक मथुरा रोड पर ट्रैफिक से काफी राहत मिल सकती है। इस प्रॉजेक्ट के अंतर्गत पुराना किला रोड से रिंग रोड तक प्रगति मैदान होते हुए 1.1 किलोमीटर की सुरंग भी प्रस्तावित है। 6 लेन की इस सुरंग से आईटीओ से होकर गुजरने वाला 60,000 कारों का ट्रैफिक और भैरों मार्ग पर 55,000 कारों का रोजना ट्रैफिक कम हो सकता है। इस प्रॉजेक्ट से मथुरा रोड सिग्नल फ्री हो जाएगी और यहां दिखने वाला ट्रैफिक जाम खत्म हो जाएगा। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन के एक अधिकारी ने कहा कि हम चाहते हैं कि पहले प्रगति मैदान के आसपास के इलाके में भीड़भाड़ कम की जाएगी, इसके बाद रीडिवेलपमेंट किया जाए। इस प्रॉजेक्ट में लगभग 777 करोड़ की लागत आएगी।

जल्द ही इस योजना पर शुरू हो जाएगा काम, मिलेगी राहत

यह टनल 100 मीटर चौड़ी होगी और इसमें 6 लेन होंगे। इंडिया गेट से आने वाली कारों के लिए इस टनल से होकर एक 48,00 कारों की क्षमता वाली पार्किंग भी होगी। जॉइंट कमिश्नर (ट्रैफिक) आलोक कुमार ने कहा कि जल्द ही इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा। आईटीओ से होकर साउथ की तरफ जाने वाला ट्रैफिक मथुरा रोड पर जाता है। टनल से यह ट्रैफिक कम हो जाएगा और भैरों मार्ग और सुब्रमण्यन भारती मार्ग क्रॉसिंग के यू टर्न की जगह एलिवेटेड यू टर्न बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास एक और एलिवेटेड यू टर्न होगा जो अंडरग्राउंड पार्किंग की एंट्री से जुड़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट के पास सड़क किनारे पार्किंग पर रोक लगाई जाएगी। ह्नअक्ष अधिकारी का कहना है कि इस कदम से इलाके में प्रदूषण भी कम होगा।

महिला शोषण खबरे खबरिया चैनल से नदारद

महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधियों का रिकॉर्ड रखने वाला 9वां देश बना भारत

(प्रेषक लेख - डॉ. नेहा नेमा) देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के दोषियों की निजी जानकारी को डेटा के रूप में रखने गुरुवार से नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सेक्शुअल ऑफेंडर्स शुरुआत कर रहा है। इस शुरुआत के साथ ही भारत दुनिया का 9वां ऐसा देश बन जाएगा जो इस तरह का डेटा तैयार करते हैं। दरअसल सरकार को यह इसलिए करना पड़ा क्योंकि 2015 की तुलना में 2016 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में करीब तीन फीसदी की बढ़ोतरी हुई जबकि बलात्कार की घटनाओं में 12 फीसद बढ़त हुई है। भारत की इस सूची में अपराधियों के नाम, फोटो, पता, फिंगरप्रिंट, डीएनए सैंपल, पैन और आधार नंबर दर्ज होंगे। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस सूची में करीब 4.5 लाख मामले होंगे, जिसमें पहली बार अपराध करने वालों से लेकर बार-बार अपराध करने वालों के नाम होंगे। देशभर की जेलों से इसके बारे में जानकारी हासिल की गई है। यौन अपराधियों की रजिस्ट्री को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो मेंटेन करेगी। अधिकारी के मुताबिक, इस रजिस्ट्री के जरिये कानून व्यवस्था का पालन करने में लगी एजेंसियों को बार-बार अपराध करने वालों की पहचान करना आसान होगा, जबकि लोग भी यौन अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के बारे में जागरूक हो सकेंगे। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2015 में दुष्कर्म के 34,651 दर्ज किए गए थे। वहीं, वर्ष 2016 में यह संख्या बढ़कर 38,947 पर पहुंच गए। वहीं, महिलाओं के खिलाफ सभी अपराधों की बात करें, तो वर्ष 2015 में तीन लाख 29 हजार 243 मामले दर्ज किए गए, जबकि वर्ष 2016 में इनकी संख्या बढ़कर तीन लाख 38 हजार 954 पहुंच गई। केवल सज़ा से यौन अपराध कम हो सकता है? डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म 'इंडियाज़ डॉटर' ने असहज सवालों की एक लंबी फेहरिस्त सामने लाकर रख दी है. यह डॉक्यूमेंट्री यौन अपराधों के सिलसिले में दोषी करार दिए गए अपराधियों की यौन विकृतियों और सोच पर रोशनी डालती है. यौन अपराध पर बहस

शुरू हो गई है और लोग इस मुद्दे पर बंटे हुए हैं कि इस फ़िल्म को दिखाने का क्या यह सही समय था, महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर इससे भारत की साख पर क्या असर पड़ेगा? लेकिन यौन अपराध एक मानसिक बीमारी भी है. ऐसे में क्या भारत के मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक-2013 में मनोविकृत यौन अपराधियों के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं? इसमें कोई शक़ नहीं कि समाज की सोच में बदलाव से हालात बदलेंगे लेकिन ऐसा होने में एक उम्र गुज़र जाएगी, इस बात को लेकर गहरी फिक्र होती है कि भारत में आज यौन अपराधियों से निपटने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली के अलावा किसी और ज़रिए की गुंजाइश बहुत कम ही है, जैसा इस मामले में हुआ.जहां ऐसे दूसरे उपाय हैं वहाँ भी ऐसा कोई कानूनी उपाय नहीं है जिससे अपराध करने वाले व्यक्ति को दिमागी इलाज या अन्य किसी तरह से सहायता लेने के लिए बाध्य किया जा सके.पुनर्वास कार्यक्रम में इस तरह के किसी विशेष पुनर्वास कार्यक्रम के अभाव में अपराध फिर से करने के मामले और इसके दोबारा साबित होने की दर पहले से ज्यादा बनी रहती है. खासकर रिहा होने के पहले साल में यौन अपराधियों के पुनर्वास से जुड़े कार्यक्रम में उनके ख़तरे, जरूरत और प्रतिक्रिया के सिद्धांतों का ख्याल रखा जाता है. इससे फिर से अपराध करने के मामलों में बड़े पैमानों पर कमी होती है ? अधिक और बीच के स्तर के खतरे वाले यौन अपराधियों को पुनर्वास कार्यक्रम से सबसे अधिक फायदा होता है, आपराधिक व्यवहार यहां तक कि यौन अपराधी के 'असामाजिक व्यवहार की समस्या' को इसकी 'कानूनी परिभाषा' के दायरे में शामिल कर भी दिया जाता है तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत दोषी ठहराए गए अपराधी को फ़ॉरेंसिक अस्पताल भेजा जा सके, जहां उनके आपराधिक व्यवहार का मूल्यांकन और इलाज किया जाए. अगर ऐसा प्रावधान होता तो उनकी रिहाई को उनके व्यवहार को फिर से अपराध करने के खतरे से जोड़ कर देखा जाता. वे लोग जो इलाज में सहयोग नहीं करते तो समुदाय में उन पर नज़र रखी जा सकती और खतरे का कोई निदान नहीं दिखता तो उन्हें दोबारा से अस्पताल भेजा सकता. गंभीर खतरा हालांकि इससे संबंधित नया विधेयक 'मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति' के इलाज के अधिकार का प्रावधान करता है ? लेकिन इसमें ऐसे अपराधी की बात नहीं कही गई है जो इलाज के बारे में कोई फैसला कर सकने की स्थिति में नहीं हैं और जो दूसरे लोगों के लिए गंभीर खतरा बने हुए है ? जो अपराधी इलाज का फैसला लेने की स्थिति में हैं लेकिन इसके लिए सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनको लेकर भी नया कानून साक्ष्य आधारित अनिवार्य इलाज का प्रावधान करने में नाकाम रहा है ? जोखिम की स्थिति इस विधेयक में यह संभावना है कि मानसिक रूप से बीमार अपराधियों से जुड़ी खामी को दूर किया जा सकता है और इसके साथ ही देश में फ़ॉरेंसिक साइक्रेट्री (मनोचिकित्सा) से जुड़ी सेवाओं की फौरी शुरुआत का रास्ता निकाला जा सकता है ? अपने मौजूदा स्वरूप में इस कानून से बहुत कम उम्मीद है,कि समाज में यौन अपराधियों के खतरे का निदान निकल पाएगा ? समस्या के समुचित मूल्यांकन को नजरअंदाज करने से कानून बनाने वालों और इसे लागू करने वालों के लिए जोखिम की स्थिति बन गई है ? मौजूदा स्वरूप में इस विधेयक से यौन अपराधियों पर कोई लगाम लगने की संभावना कम ही है ?

महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि वो सभी मुद्दों पर बातचीत को तैयार है, जिसमें आतंकवाद भी शामिल होगा। उनका ही सुझाव था कि दोनों विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा से परे बातचीत से इसकी शुरु आत करें। इस पत्र के आधार पर भारत ने निर्णय लिया कि सुषमा स्वराज कुरैशी से मिलेंगी। इधर भारत ने मुलाकात का निर्णय लिया और उधर पाकिस्तान ने हमारे जवान के साथ ऐसी बर्बरता कि किसी का दिल दहल जाए। इससे एक बार फिर साफ हो गया कि पाकिस्तान का रवैया बदलने वाला नहीं है। यह तो नहीं हो सकता कि आप हमारे सैनिकों को घात लगाकर पकड़ें, उसे यातना दें, उसके हाथ काटें।

सतीश पेडणोकर

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 20 सितम्बर को ऐलान किया कि भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात करेंगे तो देश ने उसे हैरत से देखा। यह समझना मुश्किल था कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत मुलाकात के लिए तैयार हो गया। जिस सरकार ने सार्क सम्मेलन तक इस्लामाबाद में नहीं होने दिया वह मुलाकात की टेबुल पर बैठे यह सामान्य समझ से परे था। हालांकि यह बताया कि मुलाकात का मतलब औपचारिक बातचीत की फिर से शुरु आत नहीं है। हो सकता है यह एक औपचारिक मुलाकात तक सीमित रह जाती। लेकिन जब आप मुलाकात करेंगे तो मुंह पर पट्टी बांधे नहीं रहेंगे। कुछ-न-कुछ तो बात होगी ही। आप इसे औपचारिक वार्ता भले न कहिए लेकिन यह उसकी शुरु आत ही होती।

पाकिस्तान के लिए यह बड़ी राहत की बात थी। बहरहाल, मुलाकात की घोषणा के 24 घंटे के अंदर ही उसे रद्द करने का फैसला ले लिया गया तो इससे दो बड़े प्रश्न उभरते हैं। आखिर यह फैसला किस जिस आधार पर लिया गया वह सही था? दूसरे, जब मुलाकात रद्द हो गई तो आगे पाकिस्तान के प्रति नीति कैसी होनी चाहिए? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि वो सभी मुद्दों पर बातचीत को तैयार है, जिसमें आतंकवाद भी शामिल होगा। उनका ही सुझाव था कि दोनों विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा से परे बातचीत से इसकी शुरु आत करें। इस पत्र के आधार पर भारत ने निर्णय लिया कि सुषमा स्वराज कुरैशी से मिलेंगी। इधर भारत ने मुलाकात का निर्णय लिया और उधर पाकिस्तान ने हमारे जवान के साथ ऐसी बर्बरता कि किसी का दिल दहल जाए। इससे एक बार फिर साफहो गया कि पाकिस्तान का रवैया बदलने वाला नहीं है।

यह तो नहीं हो सकता कि आप हमारे सैनिकों को घात लगाकर पकड़ें, उसे यातना दें, उसके हाथ काटें, पैर काटें, आंख फोड़ें, फिर हत्या करें और हम आपके साथ मेज पर बैठें। यही नहीं पाकिस्तान ने आतंकवादी बुरहान वानी सहित 20 आतंकवादियों पर डाक टिकट जारी कर दिया। यह जले पर नमक छिड़कने जैसा था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इमरान खान का असली चेहरा इससे सामने आ गया। क्या यह कोई आश्चर्य की बात है? सेना ने इमरान खान को बड़े नेता के रूप में उभारा, उनकी लड़ाई आसान करने के लिए जो संभव था पर्दे के पीछे से किया, कट्टरपंथी न्यायालय से मिलकर उनके रास्ते के सबसे बड़े रोड़े नवाज शरीफको सजा दिलवा दी और इन सबके बावजूद जब बहुमत नहीं मिला तो सरकार बनाने में भी भूमिका निभाई। जाहिर है, महत्त्वपूर्ण नीतियों यानी विदेश नीति, भारत के प्रति नीति, कश्मीर नीति, रक्षा नीति आदि में इमरान बस सेना की आवाज होंगे। क्या यह हमारे विदेश मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय को पता नहीं था? चुनाव जीतने के बाद यह कह देने से कि भारत एक कदम बढ़ाएगा तो हम दो कदम बढ़ाएंगे; हम उन्हें शांति कार्यकर्ता नहीं मान सकते। पहले कदम तो उनको बढ़ना था। और वह यही था कि आप आतंकवाद का कारखाना बंद कर उसका निर्यात रोक दीजिए। इसके बाद समस्या अपने-आप खत्म हो जाएगी। भारत को समझना चाहिए कि पाकिस्तान जो पहले था वही आज भी है और पता नहीं कब तक ऐसा ही रहेगा। आपको उनसे अलग तरीके से निपटना होगा। मेज पर बैठकर मुलाकात और बातचीत केवल समय व्यर्थ करना है। नरेन्द्र मोदी स्वयं भुक्तभोगी हैं। वे अफगानिस्तान से वापस आते समय पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफके आग्रह पर बिना कार्यक्रम के लाहौर पहुंचे। उनके घर तक गए। उसके बाद पठानकोट पर आतंकवादी हमला हो गया। उसमें शरीफने तत्काल इस तरह काम किया कि लगा शायद पाकिस्तान बदल रहा है। जेआईटी गठित की, दोषियों को सजा दिलाने का ऐलान किया, जेआईटी का भारत दौरा हुआ.. । जेआईटी के वापस जाने के बाद एनआईए को वहां जाना था लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया। पाकिस्तान से भारत को धोखा मिलने के ही ज्यादा उदाहरण है। इसमें मुलाकात के लिए तैयार होने का ही कोई कारण नहीं था। वैसे आतंकवादियों पर डाक टिकट जुलाई में ही जारी हुआ था। इसका पता विदेश मंत्रालय को होना चाहिए था।

एक तर्क यह दिया जा रहा है कि हमने दुनिया को बता दिया कि हम शांति चाहते हैं, पर पाकिस्तान केवल पीठ में छुरा घोंपता है। दुनिया की चिंता हमें क्यों है? क्या दुनिया का कोई देश हमारे लिए पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चाबंदी करने आया है या आएगा? उल्टे चीन जैसा देश आतंकवादी मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आतंकवादी घोषित करने को वीटो कर देता है। इतने कटु अनुभवों के बाद इस तरह का निर्णय होना ही नहीं चाहिए था। मुलाकात रद्द होने पर शाह महमूद कुरैशी की प्रतिक्रिया है कि अगर भारत नहीं चाहता तो हमें भी कोई जल्दी नहीं है। वे कह रहे हैं कि भारत में आम चुनाव नजदीक है जिससे आंतरिक राजनीति को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम रद्द किया गया है। अरे, कुरैशी जी, आंतरिक राजनीति में भी समस्या इसीलिए है कि आप आतंकवाद रोकने के लिए कदम उठाने को तैयार नहीं हैं। आतंकवाद रोकने के लिए किसी बातचीत की जरूरत है क्या? आप आतंकवादियों का महिमामंडन करेंगे, उनको भेजना जारी रखेंगे तो उसमें आपसे बातचीत करने वाली पार्टी के विरुद्ध जनता जाएगी ही। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के तीन जवानों की एक दिन में हत्या कर दी। पाकिस्तान ने एक शब्द निंदा का नहीं बोला। पाकिस्तान का तासीर ही भारत को नष्ट करने की उन्मादित भावना है। किंतु हमारे देश को तो समझना चाहिए। पाकिस्तान को आप अपनी आर्थिक शक्ति से क्षति पहुंचाइए। हमें भी उनके बलूचिस्तान में आजादी की लड़ाई का समर्थन करना चाहिए।

हम आतंकवादी पैदा नहीं कर सकते लेकिन अन्य तरीकों से तो उनको क्षति पहुंचा सकते हैं। क्यों न हम गिलगित-बलतिस्तान, सीमा पार कश्मीर के अन्य हिस्से, और जियो सिंध एवं मुहाजिर कौमी मूवमेंट के प्रतिनिधियों को मंच दें ताकि वो अपनी बात दुनिया के सामने रख सकें। पाकिस्तान से बातचीत मूर्खता है। उसकी जगह सठे साठ्यं समाचरेत का रास्ता ही व्यावहारिक है।

चलते चलते

सर्जिकल स्ट्राइक

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सकरुलर पर तंज करते हुए 8 नवम्बर (नोटबंदी) को भी मनाने की सलाह दे डाली। कोई अदना सा राजनीतिक समझ रखने वाला शख्स भी यूजीसी की इस पहल को सत्ताधारी दल के राजनीतिक लाभांश से जोड़कर देखेगा।

साल बाद फिर सर्जिकल स्ट्राइक (एसआर) को लेकर देश में गहमागहमी है। इस बार वजह सेना नहीं बल्कि विविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का एक सकरुलर है। सकरुलर में देश भर के विविद्यालयों को ''पीओके' के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा 29 सितम्बर 2016 को की गई संक्षिप्त सैन्य कार्रवाई को मनाने की बात कही गई है। लाजिमी है यूजीसी के इस फरमान को लेकर सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सकरुलर पर तंज करते हुए 8 नवम्बर (नोटबंदी) को भी मनाने की सलाह दे डाली। कोई अदना सा राजनीतिक समझ रखने वाला शख्स भी यूजीसी की इस पहल को सत्ताधारी दल के राजनीतिक लाभांश से जोड़कर देखेगा। किरकिरी होते देख, सरकार सफाई की मुद्रा में आ गई। और मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सकरुलर अनिवार्य नहीं है। बतातें चलें कि दो साल पहले ''एसआर' को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करने को लेकर भाजपा की काफी आलोचना हुई थी। इस पर चली गरमागरम बहस के दौरान यह बात भी सामने आई थी कि 29 सितम्बर का अभियान इस तरह का पहला अभियान नहीं था। सेना खामोशी से समय-समय पर इस प्रकार के ''एसआर' को अंजाम देते आई है। 29 सितम्बर के अभियान में नई बात यह रही की सेना/सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से और खम ठोककर माना। खैर, राजनीति से वापस यूजीसी के समझाइश वाले सकरुलर पर आते हैं। वैसे तो यूजीसी स्वायत्त संस्था है, मगर ताजा सकरुलर इंगित करता है कि उसका विवेक एचआरडी/सरकार से नियंत्रित होता है। कुछ समय बाद यूजीसी का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। इसकी जगह सरकार उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण का गठन करने जा रही है। ऐसे फरमान इसकी तस्दीक भी करते हैं। सेना पर राजनीति न करने की हमारे यहां परंपरा रही है। मगर राष्ट्रवाद के राजनैतिक नफा-नुकसान के नाम पर सेना के इस्तेमाल ने इस एकता के विचार में दरार पैदा की है। चाहे जीत 1971 की हो या 1999 की; दोनों सेना और देश की सामूहिक सफलता थी। किसके शासनकाल में सेना ने परचम फहराया, वह महत्त्वपूर्ण नहीं रह जाता। ''देश की बात' पर एका रहे, इसके लिए सेना के मामलों को राजनीति से दूर ही रखने में समझदारी है। और यही देश हित में भी है।

फोटोग्राफी...

यह फोटो स्विट्जरलैंड की रुयेर झील का है, जो किसी को भी हैरानी में डाल सकता है। यह झील बुल्ह क्षेत्र के विशाल रिर्ज़ावायर का हिस्सा है, जहां कुछ महीने पहले दूर तक पानी ही पानी था, लेकिन अब यह झील सूख चुकी है। इस कारण रोजाना चलने वाली नौकाएं भी कई दिन से अपनी पार्किंग में ही हैं। झील और रिर्ज़वायर की वास्तविक स्थिति दिखाने के लिए वहीं के फोटोग्राफर वेलेन्टिन फ्लुराड ने यह फोटो क्लिक किया। उन्होंने बताया कि झील में अब पानी की कुछ धारा बह रही है, जबकि यह पूरे साल भरी रहती थी। संभवत: दशकों बाद ऐसा दृश्य बना है जो चिंतनीय है। पर्यावरण वैज्ञानिकों भी इस झील का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि उसका जलस्तर 15-20 मीटर कम हो चुका है। इसमें ग्लेशियरों से पानी आता था। वहां से पानी आना बंद हो चुका है यानी ग्लेशियर से बर्फ पिघल चुकी है। theeagle.com

मौत की खबरें,

प्रधानमंत्री जी, आपकी साख और विश्वसनीयता पर कुछ गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। कम-से-कम प्रधानमंत्री पद की साख को बनाए रखने के लिए ही सही, कुछ सफाई तो देश को दीजिए। करीबी एक प्रमुख नियंतग्र समस्या है, जिससे आज अधिकतर देश जूझ रहे हैं। गरीबी का मतलब है गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीना। किसी भी स्वतंत्र देश के लिए गरीबी एक बहुत शर्मनाक स्थिति है। ऐसे में भारत ने अपने लोगों को गरीबी के दलदल से निकालने की दिशा में लंबी छलांग लगाई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की ओर से जारी मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स (एमपीआई) 2018 के मुताबिक, साल 2005-06 से लेकर 2015-16 के बीच (10 वर्षों में) गरीबी दर घटकर आधी रह गई है, जोकि 55 फीसद से घटकर 28 फीसद हो गई है। खास बात यह है कि कुल 27.1 करोड़ लोग गरीबी के दलदल से निकले हैं और यह आंकड़ा इंडोनेशिया की आबादी से थोड़ा ही ज्यादा है। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि गरीबी कम करने की दिशा में पहल करने वाले देशों में दुनियाभर में भारत समेत दक्षिण एशियाई देश सबसे आगे हैं। यूएनडीपी ने ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (ओपीएचआई) के साथ मिलकर यह इंडेक्स तैयार किया है। गौर करने वाली बात यह है कि मुस्लिम, दलित और एसटी वर्ग के लोगों ने इस क्रम में सबसे ज्यादा विकास किया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक दशक में भारत में तेजी से कम हो रही गरीबी का अहम ट्रेंड यह रहा कि समाज के सबसे गरीब तबके की स्थिति में खासा सुधार हुआ है। इतना ही नहीं साल 1900 के बाद से भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के अन्य देशों में लोगों के जीवन जीने की प्रत्याशा 4 साल बढ़ी है और भारत में लोगों के जीवन जीने की प्रत्याशा 11 साल बढ़ी है। यह बहुआयामी गरीबी से सुधार के लिए अच्छा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को गरीबी घटाने की दिशा में बड़ी कामयाबी मिली है। ताजा मानव विकास सूचकांक में भारत 189 देशों में एक स्थान ऊपर चढ़कर 130वें स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि अब भी 36 करोड़ से ज्यादा लोग किसी-न-किसी रूप में गरीबी झेल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1990 से 2017 के बीच सकल राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में 266.6 फीसद का इजाफा हुआ है।

भारत की क्रय क्षमता के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय करीब 4.55 लाख रुपये पहुंच गई है, जो पिछले साल से 23,470 रु पये अधिक है। देश में गरीबी की दर घटने को लेकर लोगों की यह धारणा कुछ हद तक सही हो सकती है कि केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का इस आंकड़े में योगदान है। लेकिन इन योजनाओं से कितना और किस तरह गरीबी दर में कमी आ रही है, यह दावा एक तरह के विवाद को ही जन्म दे रहा है, साफ है, एक तरफ तो विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था होने की आत्ममुग्धता तो वहीं दूसरी तरफ विश्व के एक तिहाई गरीबों को अपने दामन में समेटे रहने का कलंक। भारत की यह विरोधाभासी छवि वाकई सोचने को बाध्य कर देती है। बुलेट ट्रेन का सपना संजोते इस देश ने दूसरे देशों के उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने की क्षमता तो अर्जित कर ली किन्तु वह गरीबी के अभिशाप से मुक्त नहीं हो सका। इसे दुर्भाग्य ही कहें कि भारत में हर साल गरीबी उन्मूलन और खाद्य सहायता कार्यक्रमों पर अरबों रुपये खर्च किए जाते हैं। फिर भी भारत की 125 करोड़ की आबादी में 28 फीसद लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। बेशक आज देश में अनाज का कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी गरीबी, भुखमरी से लोग मर रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है?

अपनी ही बात काट रहे हैं ओलांद, राफ़ेल सौदा रद्द करने का सवाल नहीं : जेटली

निई दिल्ली (एजेंसी)।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राफ़ेल लड़ाकू विमान सौदा रद्द करने से इनकार करते हुए कहा है कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद इस सौदे पर विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। जेटली ने रविवार को फ़ेसबुक पोस्ट में लिखा है कि न भारत और न ही फ्रांस सरकार की दसॉल्ट द्वारा रिलायंस को भागीदार चुनने में कोई भूमिका रही है। राफ़ेल सौदे पर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद के बयान के बाद भारत में भारी राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। ओलांद ने कहा था कि राफ़ेल लड़ाकू जेट निर्माता कंपनी दसॉल्ट ने आफसेट भागीदार के रूप में अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस को इसलिए चुना क्योंकि भारत सरकार ऐसा चाहती थी। विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाई है और साथ ही रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के इस्तीफ़े की मांग की है।

जेटली ने कहा है कि ओलांद और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान में कुछ जुगलबंदी लगती है। जेटली ने कहा, मुझे हैरानी है कि 30 अगस्त को राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि राफ़ेल सौदे पर फ्रांस में धमाका होने वाला है। उन्हें इस बारे में कैसे पता चला? जेटली ने कहा, हालांकि मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन संदेह पैदा होता है। निश्चित रूप से कुछ है। एक बयान (ओलांद से) आता है, उसके बाद में उसका खंडन आता है। लेकिन उन्होंने (गांधी) 20 दिन पहले ही यह कह दिया था।

जेटली ने कहा कि राफ़ेल लड़ाकू विमान सौदा रद्द करने का सवाल नहीं उठता। यह सौदा देश की रक्षा जरूरत को पूरा करने के लिए किया गया है। जेटली ने कहा, कोई प्रश्न नहीं उठता। यह फौज की आवश्यकता है। ये देश में आना चाहिए और ये आएगा। रक्षा बलों को इसकी जरूरत है। इससे पहले फ़ेसबुक पोस्ट में जेटली ने लिखा कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति का पहला बयान राहुल गांधी ने जो अनुमान जताया था उससे मेल खाता है। उन्होंने कांग्रेस नेता पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सार्वजनिक संवाद करना कोई लाफ्टर चैलेंज नहीं है।

उन्होंने कहा, आप जाकर किसी के गले मिलते हैं। उसके बाद आप आंख मारते हैं। 4-6-10 बार झूठ बोलते हैं। आपकी भाषा में बुद्धिमत्ता दिखनी चाहिए। आपत्तिजनक भाषा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ठीक नहीं है। जेटली ने कहा कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद के बयान के आधार पर एक विवाद खड़ा किया जाता है। ओलांद ने कहा कि दसाल्ट एविएशन के साथ रिलायंस डिफेंस की भागीदारी भारत सरकार के सुझाव के तहत की गई। वित्त मंत्री ने कहा उन्होंने (ओलांद) बाद में अपने वक्तव्य में कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि भारत सरकार ने रिलायंस डिफेंस के लिए कोई सुझाव दिया। भागीदारों का चुनाव खुद कंपनियों ने किया। सच्चाई दो तरह की नहीं हो सकती है।

हालांकि, बाद में फ्रांस सरकार और दसॉल्ट एविएशन ने पूर्व राष्ट्रपति के पहले दिए बयान को गलत ठहराया है। जेटली ने कहा, फ्रांस सरकार ने कहा है कि दसॉल्ट एविएशन के आफसेट करार पर फैसला कंपनी ने किया है और इसमें सरकार की भूमिका नहीं है। जेटली ने कहा कि दसॉल्ट खुद कह रही है कि उसने आफसेट करार के संदर्भ में कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ अनेक करार किए हैं और यह उसका खुद का फैसला है। वर्ष 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ 58,000 करोड़ रुपए में 36 राफ़ेल लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता किया था। उस समय ओलांद फ्रांस के राष्ट्रपति थे।

शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 537 अंक की भारी गिरावट के साथ हुआ बंद

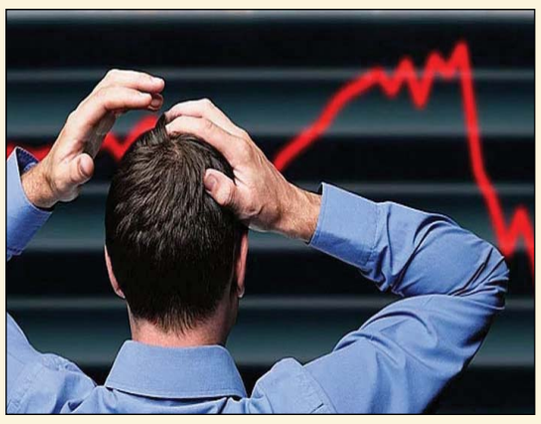

मुंबई। जब आज सुबह शेयर बाजार खुला तो उसमें गिरावट देखी गयी, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार की शुरुआत की और कारोबार की समाप्ति पर भी ये बढ़त बनाने में नाकामयाब रहा। गिरावट के इस माहौल में कारोबार की समाप्ति पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का तीस शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 536.58 अंक यानि 1.46 प्रतिशत की गिरावट के साथ 36,305.02 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की तरह ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के पचास शेयरों वाले निफ्टी पर भी कारोबार की समाप्ति पर गिरावट हावी रही और ये 175.70 अंक यानि 1.58 प्रतिशत की गिरावट के साथ 10,967.40 के स्तर पर बंद हुआ।

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को जब सुबह शेयर बाजार में कारोबार शुरू हुआ तो इसमें अच्छी बढ़त देखने को मिली और कारोबार की समाप्ति पर ये गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुआ। काराबोर की शुरुआत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का तीस शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 313.95 अंक यानि 0.85 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 37,435.17 के स्तर पर खुला और काराबोर की समाप्ति पर ये 279.62 अंक यानि 0.75 प्रतिशत की गिरावट के साथ 36,841.60 के स्तर पर बंद हुआ।

वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का पचास शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी भी काराबोर की शुरुआत में 92.80 अंक यानि 0.83 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 11,327.15 के स्तर पर खुला। सेंसेक्स की तरह निफ्टी पर भी कारोबार की समाप्ति पर गिरावट हावी रही और ये 91.25 अंक यानि 0.81 प्रतिशत की गिरावट के साथ 11,143.10 के स्तर पर बंद हुआ।

40 प्रतिशत कंपनियों की राय, ब्याज दरें और बढ़ा सकता है रिजर्व बैंक : सर्वे

नई दिल्ली। देश की 40 प्रतिशत से अधिक कंपनियों का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक चालू वित्त वर्ष में ब्याज दरों में और वृद्धि कर सकता है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आयी है। सीआईआई ने कंपनियों के भरोसा सूचकांक (बीसीआई) की त्रैमासिक रिपोर्ट के 104वें संस्करण में यह आकलन पेश किया है। सीआईआई के जुलाई - सितंबर 2018 अवधि के इस सर्वेक्षण में विभिन्न आकार और क्षेत्र की करीब 200 कंपनियां शामिल हैं। बीसीआई के आंकड़े दिखाते हैं कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनियों की अच्छे दिनों के फिर से लौटने की उम्मीद सामान्य स्तर से अधिक है। यह कारोबारी दृष्टिकोण और भविष्य में वृद्धि के प्रति बढ़ते भरोसे को दिखाता है। सीआईआई ने बयान में कहा कि पिछली दो द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि की है। सर्वेक्षण के अनुसार 42 प्रतिशत कंपनियों का मानना है कि चालू वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक ब्याज दर आगे और बढ़ा सकता है जबकि पिछले सर्वेक्षणों में कंपनियों ने ब्याज दरों में कटौती या परिवर्तन नहीं होने का अनुमान जताया था। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक के गर्वनर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समीक्षा समिति चालू वित्त वर्ष के लिए अपनी चौथी द्विमासिक समीक्षा बैठक तीन अक्टूबर से शुरू करेगी और इसका निर्णय पांच अक्टूबर को होगा।

अमेरिकी आइसक्रीम ब्रांड की भारत में विस्तार करने की योजना

नई दिल्ली। अमेरिकी आइसक्रीम ब्रांड कोल्ड स्टोन क्रीमरी ने बढ़ती मांग के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में कारोबार का विस्तार करते हुए वर्ष 2022 तक 150 आउटलेट शुरू करने की योजना बनाई है। इस ब्रांड का भारत में संचालन करने वाली कंपनी टेबल्ज़ ने गुरुग्राम में अपने फ्लैगशिप आउटलेट कोल्ड स्टोन क्रीमरी का शुभारंभ किया। यह दिल्ली - एनसीआर में अमेरिकी आइसक्रीम ब्रांड का तीसरा आउटलेट है। टेबल्ज के प्रबंध निदेशक अदीब अहमद ने इस मौके पर कहा कि विश्व के 30 से अधिक देशों में बिक रहे इस ब्रांड की अब भारतीय बाजार में भी उपस्थिति बढ़ाने की योजना बनायी गयी है। भारत में प्रीमियम आइसक्रीम सेगमेंट और स्वाद को लेकर लोगों में जागरूकता काफी बढ़ी है, साथ ही महानगर एवं टियर-1 शहरों में इसका तेजी से विकास हो रहा है। इस साल पूरे देश में 10 नए स्टोर शुरू किए जा रहे हैं और वर्ष 2022 तक आउटलेटों की संख्या बढ़ाकर 150 करने की योजना है। उन्होंने दावा किया कि उनके इस ब्रांड के आइसक्रीम में सिर्फ डेयरी उत्पादों का उपयोग किया जाता है। कोल्ड स्टोन क्रीमरी अपने स्टोर के भीतर बेहतरीन अनुभव के साथ-साथ भारतीय शिष्टता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का मिश्रण प्रदान कराता है। स्टोर में ग्राहक अपने अनुभवों के आधार पर भी उत्पाद को तैयार कराने के लिए स्वतंत्र हैं।

सरकार के कदमों से रुपये की गिरावट थमने की संभावना कम : मूडीज

नई दिल्ली (एजेंसी)।

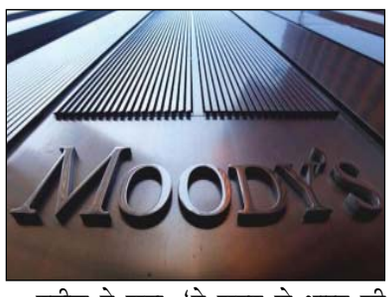

देश में पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिये सरकार की ओर से घोषित पांच-सूत्रीय रणनीति से रुपये की गिरावट के थामने की संभावना नहीं है। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने सोमवार को यह बात कही। भारत सरकार का मानना है कि मसाला बांड को विदहोल्डिंग टैक्स से छूट देने और भारतीय बैंकों को बाजार-निर्माता(प्रतिभूति बाजार में खरीद फरोख्त करने वाला) बनाने की इजाजत समेत उसके द्वारा उठाए गए विभन्न कदमों से चालू वित्त वर्ष में देश में विदेशी पूंजी का का 8 से 10 अरब डॉलर के बराबर प्रवाह बढ़ेगा जो जीडीपी के 0.3-0.4 प्रतिशत के बराबर होगा। सरकार ने अनावश्यक आयात पर अंकुश लगाने की भी मंशा भी जाहिर की है और राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है।

मूडीज ने कहा, 'ये कदम से भारत की वित्तीय साख के लिए अच्छे हैं लेकिन इसके रुपये की गिरावट को थामने की कम ही संभावना है।÷जनवरी 2018 से डॉलर के मुकाबले रुपया 10 प्रतिशत से अधिक गिर गया है। 21 सितंबर को यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 72.1 रुपये प्रति डॉलर पर रहा। मूडीज ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूती रुपये की विनिमय दर की मौजूदा कमजोरी के कारण वित्तीय साख के जोखिम को दूर रखेगी।

एजेंसी ने कहा है, 'सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का पूंजी प्रवाह पर प्रभाव पड़ने में समय लग सकता है। इसके अलावा इन संभावित उपायों से थोड़े समय के लिये रुपये पर दबाव भी कम हो सकता है।' मूडीज ने कहा कि गैर-जरूरी चीजों के आयात पर अंकुश लगाने से आयात बिल को कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन इसका प्रभाव देर से देखने को मिलेगा। वर्तमान में, भारत का चालू खाते का घाटा 2013 की तुलना में काफी कम है। उस वर्ष यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के पांच प्रतिशत के आसपास था। उस साल मई से अगस्त के बीच डालर के मुकाबले रुपया 20 प्रतिशत गिरा था। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में चालू खाते का घाटा बढ़कर जीडीपी के 2.4 प्रतिशत पर पहुंच गया है। चालू खाता घाटा देश में आने वाली और देश से बाहर जाने वाली कुल विदेशी मुद्रा के अंतर को कहते हैं।

चीन के निर्यात को नुकसान पहुंचाने वाला ट्रंप का नया शुल्क लागू

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीन से आयातित 200 अरब डॉलर की वस्तुओं पर लगाया गया नया शुल्क सोमवार से प्रभावी हो गया है। इसके साथ व्यापार मोर्चे पर लड़ाई आगे बढ़ चुकी है। ट्रंप प्रशासन अब तक चीन से आयातित 250 अरब डॉलर की वस्तुओं पर शुल्क लगा चुका है। यह अमेरिका को होने वाले चीन के निर्यात का करीब-करीब आधा हिस्सा है।

ट्रंप ने चीन को धमकी दी थी अगर उसने अमेरिकी उद्योगों को नुकसान पहुंचने वाली नीतियों में बदलाव करने से मना किया तो वह चीन से होने वाले पूरे आयात पर शुल्क लगायेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पाम्पियो ने फॉक्स न्यूज से रविवार को कहा, ÷हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। हम एक नतीजे को प्राप्त करने जा रहे हैं जो कि चीन को वैश्विक शक्ति की तरह व्यवहार करने पर मजबूर करेगा। यदि आप वैश्विक शक्ति बनाना चाहते है तो आपको पारदर्शी, कानून का पालन करना होगा, आप बौद्धिक संपदा की चोरी नहीं कर सकते।÷ अमेरिका के शुल्क के जवाब में चीन ने भी अमेरिका से आयातित 60 अरब की वस्तुओं पर सोमवार से ही शुल्क लगाने की घोषणा की थी। इस तरह चीन अब तक अमेरिका से आयात होने वाले कुल 110 अरब डॉलर के आयात सामान पर शुल्क लगा चुका है। कुल मिलाकर अमेरिका से होने वाले चीन के समूचे आयात पर शुल्क लग चुका है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि दोनों देशों के बीच जारी व्यापार वार्ता का अंत होता हुआ प्रतीत हो रहा है। चीन ने अमेरिका जाने वाले अपने प्रतिनिधिमंडल की यात्रा को रद्द कर दिया। इनके 27-28 सितंबर को अमेरिका जाने की उम्मीद थी।

5जी स्पेक्ट्रम के लिये नीलामी 2019 की दूसरी छमाही में संभव : सचिव

बेंगलूरु (एजेंसी)।

दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने रविवार को कहा कि 5जी सेवाओं के लिये स्पेक्ट्रम नीलामी 2019 की दूसरी छमाही में हो सकती है। सुंदरराजन ने यहां पीटीआई से कहा, 'वर्तमान स्थिति के मुताबिक यह (5जी स्पेक्ट्रम आवंटन) अगले साल की दूसरी छमाही में होने की उम्मीद है।'उन्होंने कहा कि 5जी सेवाओं से दूरसंचार कंपनियों को तेजी से बदलती बाजार परिस्थिति और अगली पीढ़ी की मोबाइल सेवाओं में मौजूद बेहतर कारोबारी संभावनाओं का लाभ लेने में मदद मिलेगी और वह इस क्षेत्र में अपनी बेहतर उपस्थिति दर्ज करा सकेंगी। सेवा को लेकर मौद्रीकरण परिवेश और संभावनाओं की उचित ढंग से पहचान करने में जो समय लगता है उसके बाद सेवा के क्रियान्वयन में ज्यादा समय नहीं लेगा, क्योंकि इसके लिये दूरसंचार हार्डवेयर को उन्नत करने की जरूरत नहीं होगी जैसा कि 3जी से 4जी के लिये करना पड़ा था। सुदरराजन ने कहा, '5जी सेवायें पूरी तरह से सॉफ्टवेयर के सहारे चलेंगी। इसके लिये आपको साफ्टवेयर बदलने की जरूरत नहीं है ... इसलिये यह तेजी से आगे बढ़ सकता है।' दूरसंचार सचिव ने कहा कि नीलामी से पहले दूरसंचार विभाग प्रायोगिक तौर पर स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराकर एक साल तक इसका परीक्षण कराने के पक्ष में है। इसलिये सरकार दूरसंचार कंपनियों को परीक्षण लाइसेंस देना चाहती है ताकि कंपनियां इसके लिये सभी तैयारियां पूरी कर सकें। उन्होंने कहा कि परीक्षण सुविधायें सरकार के वित्तपोषण से आईआईटी मद्रास सहित अन्य आईआईटी में तैयार हो रही हैं। एरिक्सन की परीक्षण सुविधा पहले से काम कर रही है। एक सवाल के जवाब में सुदरराजन ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के लिये 4जी सेवाओं के वास्ते स्पेक्ट्रम आवंटन पर फैसला अगले कुछ महीनों में हो जाने की उम्मीद है।

गोदरेज प्रॉपर्टीज नोएडा में आवासीय परियोजना विकसित करेगी

नयी दिल्ली। रीयल्टी कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज नोएडा में आलीशान (लग्जरी) आवासीय परियोजना विकसित करेगी। इसके लिये उसने शिप्रा समूह के साथ भागीदारी की है। कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने बयान में कहा कि यह गोदरेज प्रॉपर्टीज की नोएडा में चौथी और एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में 13वीं परियोजना है।

भारत में संतुलित और लाभप्रद विकास पर ध्यान केंद्रित : मोटोरोला

नई दिल्ली (एजेंसी)।

भारत के स्मार्टफोन बाजार में भारी प्रतिस्पर्धा से निश्चिंत मोटोरोला ने स्थानीय बाजार में नए फोन पेश करने की तैयारी की है। कंपनी ने कहा है कि वह यह अपने कारोबार को 'संतुलित और लाभप्रद' तरीके से विस्तृत करने ध्यान देगी। मोटोरोला इस समय चीनी कंपनी लेनोवो समूह का हिस्सा है। उसने ई-कॉमर्स प्लेटफार्म फ्लिपकार्ट के साथ विशेष साझेदारी में वर्ष 2014 में भारतीय बाजार में पुनप्रवेश किया। उसके बाद से, कंपनी ने अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (मंच) तथा दुकानों पर अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है।

भारत में मोटोरोला मोबिलिटी इंडिया के 'स्थानीय प्रमुख' प्रशांत मणि ने पीटीआई- बताया, 'भारतीय स्मार्टफोन बाजार हमेशा उतार चढ़ाव से भरा रहा है, हम यहां पर अपनी चुनौतियों को समझते हैं ... बाजार तेजी से बढ़ रहा है, हम उन कंपनियों के बारे में जानते हैं जो कीमत को औजार की तरह से इस्तेमाल कर रही हैं अथवा कुछ उन कंपनियों के बारे में जानते हैं जिन्होंने काफी अत्यधिक मात्रा में बाजार में निवेश किया हुआ है।'

उन्होंने कहा कि मोटोरोला की मौलिक विचार प्रक्रिया 'संतुलित और लाभप्रद वृद्धि÷ करना है। हालांकि, मणि ने कंपनी के राजस्व की मात्रा के बताने से इनकार कर दिया। अप्रैल-जून 2018 की तिमाही के दौरान भारत में कुल 3.35 करोड़ स्मार्टफोन का आयात हुआ था जिसमें ज़ियोमी की हिस्सेदारी 29.7 प्रतिशत , सैमसंग की 23.9 प्रतिशत, विवो की 12.6 फीसदी, ओप्पो की 7.6 फीसदी और ट्रांसशन की पांच प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

मनी ने कहा कि ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए उत्पादों को पेश करने के अलावा, कंपनी मोटो हब्स के साथ ऑफ़लाइन बाजार में अपनी उपस्थिति को बढ़ा रही है। मोटोरोला ने एंड्रॉइड वन सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित मोटोरोला 'वन पावर' पेश करने के लिए गुगल के साथ साझेदारी की है। इस स्मार्टफोन की कीमत 15,999 रुपये है, इसमें 6.2 इंच का डिस्प्ले, 4 जीएम का रैम, 64 जीबी इंटरनल मेमोरी (256 गीगबाइट तक विस्तार करने के योग्य), 16 एमपी + 5 एमपी दोहरा रीयर कैमरा और 12 एमपी का फ्रंट कैमरा लगा है।

प्रगति विद्यालय का अभिगम प्रयास

विद्यार्थियों को मिलेगा नि:शुल्क प्रशिक्षण

शिक्षा के साथ समाज सेवा भी

सूरत। प्रगति युवक मण्डल द्वारा संचालित प्रगति विद्यालय ने शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में एक नया अभिगम का आरंभ किया है।

गत 62 वर्षों से सेवारत प्रगति युवक मण्डल द्वारा संचालित प्रगति विद्यालय के सिल्वर जुबली महोत्सव के अवसर पर मण्डल द्वारा शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा की दिशा में एक अभिगम प्रयास किया जा रहा है। सोमवार को आयोजित पत्रकार परिषद में मण्डल द्वारा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। जिसके तहत प्रति विद्यालय के विद्यार्थियों के सर्वांगिण विकास हेतु उन्हें रोजगार विशिष्ट प्रशिक्षण नि:शुल्क दी जाएगी। जिसमें विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को आवश्यक प्रशिक्षण दी जाएगी।

जिसमें व्यूटी पार्लर, सिलाई, मेहंदी, नृत्य, योगा, कराटे, ड्राइंग, फलावर मेकींग, ग्लास पेंटींग तथा वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट इत्यादि का प्रशिक्षण शामिल है। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ 25 सितंबर 2018 को प्रात: 11 बजे शहर के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद सी.आर.पाटील, सासंद दर्शनाबेन जरदोश, शहर भाजपा प्रमुख नितिन भाई भजिया वाला द्वारा किया जाएगा। महापौर डॉ. जगदीश भाई पटेल की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक अरबिंद भाई राणा तथा विधायक कांतिभाई बलर मौजूद रहेंगे। अतिथि विशेष के तौर पर नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के पूर्व चेयरमैन हितेन्द्र भाई चुडावाला तथा ट्राफिक एजुकेशन ट्रस्ट सचिव अशोकभाई कानूनगो शिरकत करेंगे।

कापोद्रा में वायरमैन पर तलवार से हमला

सूरत। कापोद्रा नवी शक्ति नगर सोसायटी के पास शनिवार रात को वायरमैन पर पुलिस का खबरी होने का वहम रखकर तीन लोगों ने तलवार से हमला किया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हीराबाग धरतीनगर के पास नवी शक्ति सोसायटी में रहनेवाले प्रभाशंकर मिश्रा वायरमैन का कार्य करते हैं। प्रभाशंकर शनिवार रात को अपनी सोसायटी के पास खड़ा था। तभी उसकी ही सोसायटी में रहनेवाले कमलेश उर्फ कमला, अनिल खटीक और सतला उसके पास आए थे और प्रभाशंकर को कहा कि तू पुलिस का खबरी है। ऐसा कहकर सिर में तलवार मार दिया। इस बार प्रभाशंकर को बचाने के लिए ऑमलेट की लारी चलानेवाले बाबु उर्फ जीतेन्द्र बीच में आने से उसे भी गैस का चूल्हा मारकर घायल कर दिया और घटना के संबंध में पुलिस केस करने पर जान से मारने की धमकी दी।

युवक पर चाकू से जानलेवा हमला

सूरत। शहर के वेसू इलाके में युवक पर चाकू से तीन लोगों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने की घटना प्रकाश में आयी है। उमरा पुलिस सूत्रों के अनुसार वेसु सिद्धिविनायक मंदिर के पास पालिका आवास निवासी मोहम्मद समीर ममजीम गत रोज शाम को घर के पास खड़ा था तभी टीनु समेत तीन लोगों उसके पास आकर झगड़ा करने लगे। इस बीच उन्होंने अपने पास रखा चाकू निकालकर मोहम्मद के पेट और पीठ में वार कर घायल कर दिया। घटना की शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है।

गुजरात में फिर तेज होगा पाटीदार आंदोलन

पास-एसपीजी की बैठक में फैसला

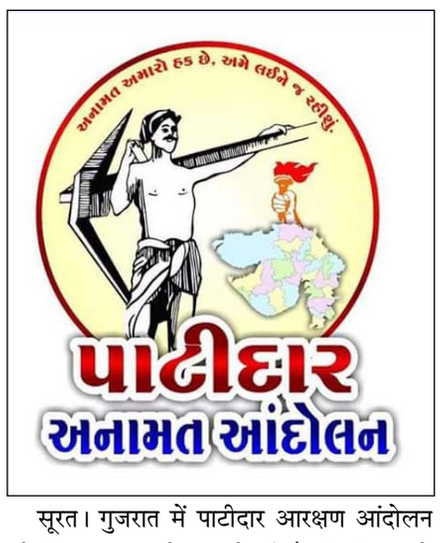

सूरत। गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन को फिर एक बार तेज करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सूरत में आज पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति (पास) और सरदार पटेल ग्रुप (एसपीजी) की बैठक हुई। जिसमें आगामी दिनों में पाटीदार आंदोलन को तेज करने का फैसला किया गया है। बैठक में एसपीजी प्रमुख लालजी पटेल समेत राजकोट, मेहसाणा, कच्छ, अहमदाबाद इत्यादि से पास और एसपीजी नेता शामिल हुए।

सूरत के पास कन्वीनर धार्मिक मालविया के मुताबिक अल्पेश कथीरिया समेत 7 पाटीदार युवक जेल में है, जिनकी रिहाई के साथ आनेवाले दिनों में राज्य की प्रत्येक तहसील में तहसीलदार और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। 2 अक्टूबर को प्रत्येक जिला और तहसील मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा। इसके बावजूद मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो विधायकों और मंत्रियों के सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम में बहिष्कार किया जाएगा। फिर भी पाटीदारों की मांगें पूरी नहीं हुई तो विधायकों और मंत्रियों का घेराव किया जाएगा और सार्वजनिक कार्यक्रमों का विरोध किया जाएगा। इसके अलावा आगामी 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात आ रहे हैं, तब राज्यभर में उनके विरोध में कार्यक्रम किए जाने का बैठक में फैसला किया गया है।

दूसरी ओर पाटीदारों ने आज अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान भक्ति के साथ शक्ति का प्रदर्शन किया। अल्पेश कथीरिया की रिहाई की मांग को लेकर हजारों की संख्या में पाटीदार सूरत के वराछा स्थित मीनी बाजार में एकत्र हुए। जहां अल्पेश का मास्क लगाकर पाटीदार युवकों ने विशाल रैली निकाली। गणेश प्रतिमा के साथ रैली ने पाटीदार बहुल इलाकों में भ्रमण किया। सूरत के योगी चौक क्षेत्र के किरण चौक में पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति की ओर से गणेशोत्सव का आयोजन किया गया था। जिसमें पास नेता हार्दिक पटेल भी एक दिन शामिल हुए। गणेशोत्सव पंडाल में अल्पेश कथीरिया के समर्थन में रामधून समेत कई कार्यक्रम हुए। आज गणेश प्रतिमा का विसर्जन पाटीदारों की भक्ति के साथ शक्ति प्रदर्शन नजर आया।

सड़कें हैं राज्य के विकास का राजमार्ग: मुख्यमंत्री

सरखेज-गांधीनगर-चिलोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग के छह लेन चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास

अहमदाबाद। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य में सड़कों को विकास का राजमार्ग करार देते हुए कहा कि मार्ग सुविधा की आधारभूत संरचना सहित शिक्षा, स्वास्थ्य और सर्विस सेक्टर जैसे क्षेत्रों में सुविधाएं विकसित कर गुजरात ने विकास के वैश्विक मानदंड स्थापित किए हैं। सोमवार को अहमदाबाद में राज्य के मार्ग-मकान विभाग एवं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सहयोग से सरखेज-गांधीनगर-चिलोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 147 को 847 करोड़ रुपए के खर्च से छह लेन बनाने के कार्य के शिलान्यास अवसर पर उन्होंने यह बात कही। उप मुख्यमंत्री नितिनभाई पटेल सहित मंत्री भूपेन्द्रसिंह चूड़ास्मा, प्रदीपसिंह जाडेजा और गणमान्य महानुभाव इस मौके पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात ने भूतकाल में कांग्रेस की सरकारों के दौरान जिस अन्याय और विकास विरोधी मानसिकता का सामना किया है, उसकी दुगने विकास कार्यों से केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार क्षतिपूर्ति कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में केंद्र की नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने गुजरात को 30 हजार करोड़ रुपए के नेशनल हाइवे तथा 15 हजार करोड़ रुपए के कोस्टल हाइवे की मंजूरी प्रदान कर विकास की गति को और तेज बनाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की पूर्व की कांग्रेस नीत यूपीए की सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई थी। सरकार की तिजोरी में सुराख हो चुके थे और जनता के पैसे विकास एवं जनहित के कार्यों में खर्च होने के बदले गायब हो जाते थे। उन्होंने कहा कि मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभालते ही पारदर्शी, स्वच्छ एवं सुशासन युक्त शासन प्रदान कर तिजोरी के सभी सुराखों को भर दिया है। अब, जनता के पैसे की हर पाई जनहित में ही उपयोग होती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की सरकार में पहले केंद्र से भेजा जाने वाला 1 रुपया गांव तक पहुंचते-पहुंचते 15 पैसा हो जाता था, परन्तु अब 1 रुपए के सामने सवा रुपये का कार्य होता है। गुजरात के साथ सौतेला बर्ताव कर विकास से वंचित रखने की यूपीए सरकार की साजिश का ब्यौरा देते हुए रूपाणी ने कहा कि क्रूड ऑयल रॉयल्टी के 11 हजार करोड़ रुपए बरसों तक नहीं दिए गए, नर्मदा डैम की ऊंचाई बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी, रेलवे की नई ट्रेन नहीं दी और गेज परिवर्तन के कार्यों से राज्य को वंचित रखा।

आंखों में कांटे की तरह उन्हें चुभने वाले गुजरात के खिलाफ यूपीए सरकार ने ऐसे अनेक अन्याय किए।

बरसों से अधर में लटकी गुजरात की मांगों और समस्याओं के सुखद निवारण के लिए केंद्र की मोदी सरकार का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन की सौगात, अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा, द्वारका-बेट द्वारका को जोड़ने वाला 962 करोड़ का सिग्नेचर पुल, स्मार्ट सिटी में गुजरात के 6 शहरों का समावेश कर प्रत्येक को 500 करोड़ का आवंटन और सरदार साहब की विराटतम प्रतिमा- स्टेचू ऑफ यूनिटी जैसे विकास के अनेक प्रकल्प देकर गुजरात के विकास को नई दिशा उन्होंने दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने धोलेरा के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2800 करोड़ रुपए का आवंटन करने के साथ ही डिफेंस-नेवी के क्षेत्र में गुजरात में नई अकादमी, डीसा हवाई पट्टी का वायुसेना के एयरबेस के रूप में विकास तथा वडनगर और धोलावीरा जैसे पुरातन स्थानों के विकास के लिए केंद्रीय मदद दी है। उन्होंने कहा कि गुजरात में सर्वग्राही विकास के आयामों में च्जहां नागरिक, वहां सुविधाज्और चविवाद नहीं संवादज्के मंत्र के साथ यह सरकार न्यूनतम संसाधनों के अधिकतम उपयोग से गुजरात को अव्वल राज्य बनाने को संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छह लेन के इस महत्वाकांक्षी प्रकल्प के पूरा होने के बाद ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं रहेगी तथा फ्लाइओवर एवं रेलवे ओवरब्रिज बनने से गुजरात फाटक मुक्त गुजरात बनेगा।

गणेश विसर्जन दौरान टेम्पो को लेकर मारपीट

सूरत। गणेश विसर्जन दौरान शनिवारी बाजार डक्का ओवारा निकट टेंपो आगे लेने को लेकर एक मंडल के लोगों ने महिला समेत पांच लोगों के साथ मारपीट की।

अठवा पुलिस सूत्रों के अनुसार महीधरपुरा गलेमंडी कुंभारशेरी निवासी जयनाबेन चंद्रेश राणा गणपति का विसर्जन करने के लिए शनिवारी बाजार डक्का ओवारा पर गई थी। वहां से वापस लौटते समय जामुनी रंग के कपड़े पहने लोगों ने टेम्पो आगे लेने को लेकर झगड़ा कर महिलाओं के साथ मारपीट की। कल्पेश धनसुख राणा और कशिलाबेन प्रकाश बीच बचाव में आये तो उनके सिर में वार कर दिया। समूह ने साथ ही खुश्बुबेन राणा, राजु राणा, जतिन राणा, भीखीबेन राणा, मनीष के साथ भी मारपीट की। इसमें कल्पेश का सोने की चेन और मनीष का मोबाइल गुम हो गया। जयनाबेन ने घटनाकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवायी है। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है।

अमरोली में रूपयों के विवाद में व्यापारी पर जानलेवा हमला

सूरत। शहर के अमरोली इलाके में रूपयों के विवाद में व्यापारी पर जानलेवा हमला किए जाने की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवायी गई है। अमरोली पुलिस सूत्रों के अनुसार मोटा वराछा महादेव चौक कुदरत एपार्टमेन्ट निवासी उर्वेश कडवा पटेल व्यवसायी है। उर्वेश गत रोज शाम को घर के पास खड़ा था। तभी कार में आए अभिषेक नावडिया, रवि भाल और दिक्षीत उर्फ भूरो उसके पास आए थे और उसके छोटे भाई के साथ रूपयों लेनदेन के मामले में झगड़ा कर बेसबॉल के डंडे से मारपीट कर पैर में फ्रैक्चर कर दिया और कार का कांच तोड़ दिया।

सायण गाम हत्या के विरोध में बाजार रहा बंद

सूरत। सायण गांव में हत्या के विरोध में बाजार बंद रहा। ओलपाड के सायणगाम बाजार चौराहा पर कोली फलियु निवासी धवल जगदीश पटेल गत रोज रविवार को बाजार चौराहे पर मित्रों के साथ खड़ा था, तभी चैतन्यकुमार रावल ने धवल के पैर पर कार चढ़ा दी थी। इसको लेकर हुई तकरार में चैतन्य कुमार और उसके साथ कार में बैठे अन्य चार लोग कार से बाहर आ गए और धवल समेत उसके दोस्तों के साथ झगड़ा कर चाकू से वार कर दिया। इसमें धवल की मौत हो गई। लोग थाने में इकट्ठा होकर हत्यारे चैतन्य को सौंपने की मांग के साथ हंगामा मचाया। सोमवार सुबह धवल की लाश का सूरत में फोरेन्सिक पीएम किया गया। सोमवार को कोली पटेल समाज द्वारा सायण गाम बंद का ऐलान दिया गया था। जिसके तहत सोमवार सुबह से ही सायण गांव के बाजार बंद रहा। कोई अप्रिय घटना नहीं घटे इसके लिए चुस्त पुलिस बंदोबस्त तैनात किया था।

अलथाण में पशु पकड़ने गए पालिका कर्मियों पर पथराव

सूरत। शहर के अलथाण रोड खोडियारनगर में गत रातक को पशु पकड़ने गए पालिका कर्मियों पर पशुपालकों ने पथराव कर गाड़ी का कांच तोड़ दिया।

खटोदरा पुलिस सूत्रों के अनुसार पालिका कर्मी शनिवार रात अलथाण रोड खोडियारनगर भटकते पशुओं को पकड़ने के लिए गया था। तभी हरेश लालो, अजय नरसिंह, रतिलाल, भरत समेत 50 लोगों के समूह ने पशु पकड़ने के लिए आए पालिका के स्टाफ पर पथराव किया।

सूरत। शहर में रविवार देर रात तक चले गणेश मूर्ति विसर्जन में जहाँ श्रद्धालुओ ने बप्पा के गगनभेदी जयकारे लगते हुए श्रीजी को डूमस सहित सूरत नगर महा पालिका की ओर से बनाए कृत्रिम तालाबों सहित अपने सोसाइटियों में गाजे बाजे ढोल ताशों के साथ अगले बरस जल्दी आने का न्योता देते हुए नम आँखो से विदा करते हुए विसर्जित किया। इस मौके पर शहर की तमाम धार्मिक व सामाजिक सेवाभावी संस्थाओ ने प्रशासन की ओर से विसर्जन के लिए निर्धारित रूटों पर पंडाल लगा कर गणेश मूर्ति विसर्जन यात्रा में शामिल श्रद्धालुओ को पानी पाउच, चाय, छाछ, वडापाव, ब्रेडरोल, सहित अन्य खाद्य वस्तुओ को वितरित कर मानवीय सेवा की।

सूरत। श्याम रचना सोसायटी बेसू गत वर्ष के भांति इस वर्ष भी इको फ्रेंडली मिट्टी के गजानंद जी का विसर्जन सोसाइटी प्रांगण में किया गया।

महादेव मीडिया
रोहताश यादव 9924144499, 7015339195
वीजिटिंग कार्ड, बिल बुक, लेटर पैड, बेनर, पोस्टर, आदि का डिजाइन बनवाने के लिए संपर्क करें। (हिन्दी, गुजराती)
हिन्दी, गुजराती न्युज पेपर डिजाईन करवाने के लिए संपर्क करें।
304 केवल कॉम्पलेक्ष नवा गाम, डिंडोली, उधना सूरत।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com